नहीं है और यह जगह रिक्त बनी रहती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सेलेक्शन कमेटी में कोई शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति था? अगर इन कमेटीज में इस तरह के वर्गों के व्यक्ति नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि भविष्य में इन चयन आयोगों में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा ताकि इन वर्गों का अहित न हो सके?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Madam, as far as I know, there are six Members of this Committee. The Committee is presided over by a Judge of the Supreme Court. Then there is the Revenue Secretary and the President of the CEGAT. I think, considering the composition of the Committee, it is not possible to enlarge and make a specific reservation in the Committee Members.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is very specific. Now, Question No. 385.

Dealing with the Sickness of Cooperative Units

@@*385. SHRI SHIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL: Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in case of public limited companies, BIFR have powers to diagnose and deal with their sickness under a Sick Industrial Companies Act;

(b) whether, there is any such agency constituted by Government to deal with the sickness of Cooperative units;

(c) if so, the name of such agency and the Act under which the powers are so provided; and

(d) whether cooperative sugar units manufacturing white crystal sugar have also been covered by such act to revive from its sickness?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में दी गई परिभाषा के अनुसार, गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की रुग्णता से निपटने की शक्तियां प्राप्त हैं।

(ख) और (ग) 1985 के उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान सहकारी क्षेत्र के उद्योगों की रुग्णता पर लागू नहीं होते हैं।

(घ) यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

SHRI SHIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL: Madam Deputy Chairman, earlier there were 93,220 co-operative units in the country, out of which 75,000 were non-viable. Today, the situation is that about 1,30,000 such units are reported to be sick. Considering this wider sickness, the question was put to a Committee and the Committee recommended that a special Act should be passed to face this issue. Then the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act was passed, and under this Act, the Board for Industrial and Financial Reconstruction was nominated. This Board was given the power to consider the question of sickness and suggest measures, including the mergers, if necessary. And in the initial stages, the BIFR did not cover the public

@*Previously starred question 325, transferred from 19-8-1993.

sector units. But after that, an amendment was made, and the public sector units were included in it. I would like to know from the hon. Minister of Finance as to why the Government has not considered including in it the co-operative units in the country which are today in a very large number and which are also in a very vital sector like spinning mills and sugar factories. I would like to know whether the Government will consider including these co-operative units under the BIFR.

डा० अबरार अहमद : मेडम, यह सही है कि कोआपरेटिव सेक्टर की जो इकाइयां हैं उनको बी०आई०एफ०आर० के अन्दर शामिल नहीं किया जाता है और इसके अलावा जैसा माननीय सदस्य ने कहा, पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की जो कम्पनियां हैं उनके सिक होने से बी०आई०एफ०आर० में विचार किया जाता है। कोआपरेटिव सेक्टर की जो इकाइयां हैं उनको बी०आई०एफ०आर० के अन्दर शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही सरकार उस संदर्भ में कोई विचार कर रही है। उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि को आपरेटिव सेक्टर की जो भी इकाइयां हैं, चाहे वे शुगर के सेक्टर में हों या अन्य किसी क्षेत्र में हो उसके कोआपरेटिव का, यह कभी भी सरकार का ध्येय नहीं रहा कि वापस उसकी रिसेल हो या उसके वाइन्ड अप करने पर जोर दिया जाय। जहां तक है, अभी बी०आई०एफ०आर० के अन्दर कोआपरेटिव को शामिल नहीं किया जाता है।

SHRI SHIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL: Madam, very recently, a Committee was appointed to study the working of the BIFR. It has been reported that the BIFR is suggesting winding up of all tribunals. The most important factor reported in the press is that they are suggesting winding up and not reconstruction. While the main purpose of the BIFR is industrial finance and reconstruction, why is it that the Board is suggesting winding up? The report also suggests that it should be delinked so that these companies could be taken over by the foreign companies. I want to know whether this is the intention of the Government. If that report is accepted, it is quite likely that a large number of companies may be going into the hands of foreign companies. I would like to know what is the attitude of the Government in this regard. Secondly, in that report, it has been stated that they need not consult the State Governments before winding up. If that particular authority is given, I think, it would lead to a lot of unemployment without any protection. I would like to know from the Government what *is their attitude.*

डा० अबरार अहमद : महोदया, माननीय सदस्य ने जिस कमेटी और रिपोर्ट का जिक्र किया, मैं जहां तक समझ पाया हूं, गोस्वामी कमेटी और उसकी रिकमन्डेशन के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं। उसने जो भी रिकमन्डेशन दी है, वह सरकार के पास अंडर-कंसीडरेशन है। जहां तक बी०आई०एफ०आर० की बात है, तो उसकी कार्य-शैली, कार्य-प्रणाली बिल्कुल तय है। उसके अंदर जो भी प्रभावित पक्ष होते हैं, चाहे उसके अंदर परमोटर्स हों, मजदूर हो, बैंक्स हों या अन्य फाइनेंस करने वाले या इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट्स हों, वे सब अपना अपना पक्ष रखते हैं और किस प्रकार से वह उसके अंदर सैक्रिफाइस कर सकते हैं और उस यूनिट को पुनः वाइबल बनाया जा सकता है, वह पैकेज देते हैं। अगर यह सब को स्वीकार्य होता है तो बी०आई० एफ० आर० उसके अंदर, उसकी वाइबलिटी को देखते हुए वापस रिवाइबल का निर्णय लेता है या वाइंडिंग-अप का निर्णय लेता है। उसके मैरिट्स और डी-मैरिट्स के आधार पर फैसला होता है।

SHRI JAGESH DESAI: As the law stands today, the stand taken by the

Government is correct. But I would like to remind the House that when I raised an issue regarding neglect of the co-operative sector, the Finance Minister was kind enought to say that it was not so and that they want to help the co-operative sector. In view of that, what I have seen is that out of the cases decided by the BIFR, 68 per cent of them were found viable and only 32 per cent were not found viable. I would like to know from the hon. Minister whether for the co-operative sector, for the sick co-operative units, you are going to have some other machinery by which you can find out whether a unit is viable or not so that you give finances accordingly and the co-operative sector can also be strengthened and that is what the Minister had said. I would like the hon. Minister to react.

डा० अबरार अहमद: महोदय, माननीय सदस्य ने कोआपरेटिव सेक्टर के बारे में बात कही है। हमारा भी हमेशा कोआपरेटिव सेक्टर के लिए हेल्पफुल नजरिया रहता है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बी० आई०एफ०आर० में, जो भी कोआपरेटिव सेक्टर की सिक यूनिट्स हैं, उन पर निर्णय नहीं किया जाता है लेकिन जो भी बीमार इकाइयां हैं या जिनको फाइनेंस की आवश्यकता होती है उसमें राष्ट्रीय सहकारी, खासतौर से कोआपरेटिव सेक्टर की चीनी मिलों के बारे में सवाल है। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उसके लिए 31-7-93 तक 37 सहकारी चीनी मिलों के अधिग्रहण के लिए पैसा दिया गया है और 242.49 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है और 152.42 करोड़ रुपया उसके डिसबर्समेंट के लिए दिया गया है। इसके अलावा एन०सी० डी०सी० की जिस योजना का मैंने जिक्र किया यह कृषि मंत्रालय के अधीन आती है। उसके अलावा भी जो अलग अलग स्टेट-वाइज भी.....

SHRI JAGESH DESAI: That is not my question. My question is whether you are going to have some other machinery for the co-operative sector as you have a machinery for the private and public sector units. Are you going to have some other machinery for the co-operative sector to find out whether a unit is viable or not.

डा० अबरार अहमद: इस तरह का अभी कोई प्रपोजल नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: मैडम, कोआपरेटिव खेती को प्रोसेस करने के लिए, आमतौर पर खेती की उपज को प्रोसेस करने के लिए यह योजना इस्तेमाल में लायी जाती है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं क्योंकि सरकार कोआपरेटिव्स को पैसा देती है, फंड देती है, लोन देती है लेकिन कोआपरेटिव जो कि ब्यूरोक्रेटिक कन्ट्रोल में है—बहुत जगहों पर फारमर्स के कन्ट्रोल में है लेकिन बहुत सी जगहों पर यह ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनको कोआपरेटिव्स के कंट्रोल में रिवाइव करने के लिए वह कुछ करेंगे ताकि कोआपरेटिव ठीक ढंग से चल सकें?

डा० अबरार अहमद: उपसभापति महोदया, जहां तक माननीय सदस्य ने कोआपरेटिव की बात कही, कोआपरेटिव बनाने का उद्देश्य यही है ताकि उनका नियंत्रण स्वयं का नियंत्रण स्वयं के पास रहे लेकिन फिर भी जैसे कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि किसी तरह से ब्यूरोक्रेसी के हाथ में नियंत्रण चला जाता है या उसका एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला जाता है। कोआपरेटिव में जो भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है और उन्हीं में से अध्यक्ष भी चुना जाता है, जो प्रक्रिया है, वह यह है कि लेकिन फिर भी माननीय सदस्य जो ब्यूरोक्रेसी के बारे

में कह रहे हैं अगर कहीं उनकी जानकारी में कोई स्पेसेफिक केस हो तो बता दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : सारे नार्दर्न बेल्ट में ऐसा है।

उपसभापति : क्वेश्चन नम्बर 386।

Privileges enjoyed by the members of TAC and PAC

*386. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the names and addresses of the present members of the Telecom Advisory Committee (TAC) as well as Postal Advisory Committee (PAC) for Assam circle stating the respective interests represented;

(b) What are the details of privileges, facilities and other powers viz. sanctioning/recommending new telephone connections or opening of new telephone exchanges or expansion of their capacity enjoyed by the members of the said TAC as well as those of the said PAC;

(c) what is the tenure of the current TAC and PAC for the Assam Circle;

(d) what are the details of meetings held so far by the said TAC and PAC, meeting-wise details alongwith the recommendations made by them and those implemented by the Government, member-wise details; and

(e) what are the details of the amounts of Travelling Allowance and Daily Allowance admissible at present to the said TAC and PAC members, and the details of the amount of Travelling Allowance and Daily Allowance paid to each of the said TAC and PAC members so far during their current tenure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) The required information in respect of TAC, Assam Circle is furnished in the enclosed statement I (See below). Postal Advisory Committee for Assam Circle has not yet been constituted.

(b) The required information in respect of Telecom Advisory Committee members is furnished in the enclosed statement II (see below). Members of Postal Advisory Committee do not enjoy any privileges.

(c) The tenure of the current TAC of Assam circle will expire on 31-12-93. As regards PAC, question does not arise in view of (a) above.

(d) 3 meetings of Telecom Advisory Committee for Assam circle had taken place one each in June 92, January 93 and May 93 respectively. Apart from the normal deliberations, the members of Telecom Advisory Committee unanimously recommended as follows:

Month	Recommendations
January 93	Increase in free call limit for TAC members from 1,200 to 3,000.
May 1993	Apart from OYT and N-OYT Spl, TAC should have powers to sanction telephone connections in N-OYT General category also.

The above recommendations were not accepted as these were against the policy of the Government.

(e) Non-official members are paid Travelling Allowance and Daily Allowance at the admissible rates for actual journey from their place of residence to place of meeting in the case of TAC and PAC. In the case of PAC no expenditure was incurred as the PAC was not constituted. In the case of TAC, an amount of Rs. 31,922/- has been incurred as TA and DA of the TAC members of the current TAC so far.